जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 10 प्रभात अजमेर, गुरुवार 8 अगस्त, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

‘कोशिश मैडल जीतने की थी, या इस बात की कि कैसे फोगाट मैडल न जीत पाये?’

कांग्रेस ने सरकार पर खुला आरोप लगाया, विनेश फोगाट के ओलम्पिक में ‘‘डिस्क्वालिफिकेशन’’ के लिये

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अगस्त। आज सुबह 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया, जब उन्होंने यह खबर पढ़ी कि पैरिस गोल्ड /सिल्वर मैडल पाने की भारत की आशा धूल में मिल गई है।

विनेश फोगाट उस मुकाम पर पहुँची, जहाँ भारत की कोई महिला पहलवान पहले नहीं पहुँची थी। 2024 ओलंपिक्स में, सात घंटों के अंदर वो प्री क्वार्टर से क्वार्टर फाइनल और फिर विश्व चैंपियन को हराकर सेमी फाइनल में और उसके बाद फाइनल तक पहुँची।

उसे 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। इस खबर पर हर तरफ अविश्वास और अचरज का माहौल है। हजारों तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार को लक्ष्य बनाते हुए षड्यंत्र की थ्योरी दी है।

खेल मंत्री के जवाब से असंतुष्ट इण्डिया अलायंस और कांग्रेस नेताओं ने लोकसभा और राज्यसभा में वॉक आउट कर दिया, क्योंकि मंत्री सिर्फ आंकड़े गिना रहे थे तथा बता रहे थे कि फोगाट की ट्रेनिंग पर कितना पैसा खर्च हुआ है।

- **जैसा कि विदित ही है, फोगाट के सेमी फाइनल में कुश्ती का मैच जीतने के बाद, रजत/स्वर्ण मैडल जीतने की पूर्ण आशा थी, पर, 100 ग्राम ओवर वेट पाये जाने के कारण, फोगाट ‘‘डिस्क्वालिफाई’’ कर दी गयी।**
- **कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकारी अधिकारी, जो पेरिस ओलम्पिक में इन्तज़ामात के लिये गए थे, क्या छुट्टी मनाने ‘‘वैकेशन’’ पर गये थे तथा इन अफसरों ने क्या कुछ भी भूमिका निभाई फोगाट का मसला ऑर्गनाइज़र्स के सामने उठाने में।**
- **इंडियन ओलम्पिक ‘‘एसोसिएशन की अध्यक्ष पी.टी. ऊषा ने क्या रोल अदा किया, फोगाट को न्याय दिलाने में।**
- **पंजाब के मुख्यमंत्री मान, हरियाणा में फोगाट के घर गये, ‘‘डिस्क्वालिफाइड’’ फोगाट के परिवार से मिलने।**
- **इस वर्ष हरियाणा विधासनभा के चुनाव होने हैं और ऐसा लग रहा है, फोगाट प्रकरण चुनाव में काफी निर्णायक भूमिका अदा करेगा।**

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि रोचक बात यह है कि जब फोगाट फाइनल में पहुँची तो, न तो नरेन्द्र मोदी और न उनकी टीम ने फोगाट के समर्थन में कोई ट्वीट किया, जबकि, उसे सिल्वर या गोल्ड मैडल मिलना सुनिश्चित हो गया था, पर जब वो डिस्क्वालिवाई हो गई तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार ट्वीट किया।

कांग्रेस ने भारतीय खिलाड़ियों के दल के साथ बड़ी संख्या में पैरिस गए अधिकारियों पर भी उंगली उठाई और कहा कि क्या ये लोग छुट्टी मनाने पैरिस गए थे? फोगाट का केस उठाने में उनकी क्या भूमिका रही?

कांग्रेस ने यह भी पूछा कि पी.टी. उषा की अध्यक्षता वाली ओलंपिक एसोसिएशन ने फोगाट को न्याय दिलाने के लिए क्या किया?

कांग्रेस लगातार ये प्रश्न पूछ रही है और मोदी सरकार के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों को याद दिला रही है कि सरकार ने उन पहलवानों का कैरियर खत्म करने की धमकी दी थी, जिन्होंने 2023 में फोगाट के नेतृत्व में रैसलिंग फैडरेशन चीफ और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ यौन उत्पीड़न तथा महिला पहलवानों को शारीरिक व मानसिक कष्ट देने के आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की थी।

धरनों और प्रदर्शनों के अलावा दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों को दिल्ली की सड़कों पर घसीट कर उन्हें शारीरिक यातना भी दी थी।

कांग्रेस ने कहा, प्रधानमंत्री ने सांसद बृजभूषण के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। इसके बावजूद फोगाट ने, एक तरह से निराशा के गर्त से निकलकर, शानदार

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पांडुपोल मंदिर के लिए इलैक्ट्रिक शटल बसें चलाएगी सरकार

जयपुर, 7 अगस्त (का.सं.)। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वह साल 2025 तक सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित पांडुपोल हनुमान मंदिर में यात्रियों की आवाजाही के लिए निजी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक शटल बसें चलाएगी, जिससे टाइगर आवास और मंदिर जाने वाले दर्शनार्थियों की भावनाओं के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा राज्य सरकार बफर ज़ोन में चल रहे होटलों व रिसॉर्ट्स का भी परीक्षण करेगी और अवैध पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने बुधवार को वन व वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दिया।

- **राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आश्वासन दिया कि वर्ष 2025 तक सरिस्का टाइगर रिज़र्व के पांडुपोल हनुमान मंदिर तक यात्रियों की आवाजाही के लिए निजी वाहनों पर रोक लगा दी जाएगी और इलैक्ट्रिक शटल बसें चलाई जाएंगी।**

भारत के लिए अजनबी नहीं हैं बांग्लादेश के भावी अंतरिम चीफ

यूनुस का अक्सर भारत आना-जाना लगा रहता है, माइक्रो फायनैंसिंग पर व्याख्यान देने उन्हें बुलाया जाता है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अगस्त। बाँग्लादेश में हुये तख्तापलट के बाद, मुहम्मद यूनुस, जो कभी ‘‘गरीबों के बैंकर’’ के रूप में विख्यात थे, को अन्तरिम सरकार का प्रमुख बनाये जाने की पूरी तैयारी है। यह अन्तरिम सरकार देश की संसद के नये चुनाव होने तक सत्तासीन रहेगी।

मुहम्मद यूनुस ‘बॉग्लादेश ग्रामीण बैंक’ के संस्थापक थे, जिसने गरीबों एवं समाज के कमजोर वर्गों को, छोटे-मोटे कामधन्धे चलाने के लिये धनराशि उपलब्ध कराने नये-नये तरीके शुरू किये थे। छोटे व्यवसायों की फन्डिग के उनके बिल्कुल नये तरीकों को मान्यता देते हुये, यूनुस को नोबल शान्ति पुरस्कार से विभूषित किया गया था।

लेकिन मुहम्मद यूनुस की पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसीना से अनबन हो गई थी, और अब भी विद्यमान है। पूर्व सरकार ने यूनुस के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया था, जिसमें उन्हें जेल की सजा हुई थी।

यूनुस भारत के लिये कोई अजनबी व्यक्ति नहीं हैं तथा पूर्व भारतीय सत्ताधीशों से उनकी बातचीत होती रही थी। वे प्रायः भारत आते थे तथा भारत में आयोजित मीटिंगों और कॉन्फ्रेसों में ‘माइक्रो-फायनैंसिंग’ पर व्याख्यान देते थे। व्यवहारिक व्यवसायी होने के नाते यूनुस काफी प्रगतिवादी हैं तथा बांग्लादेश को वर्तमान अस्थिरता के दौर से निकालकर स्थिरता की ओर लाने में भारत व भारत के सहयोग को समझ सकते हैं।

पेरिस से ढाका के लिए उड़ान भरने से पहले, मोहम्मद यूनुस ने पश्चिमी प्रेस को दिये इन्टरव्यूज़ में पूर्व सत्ता एवं शासन की कड़ी आलोचना की तथा कार्यवाही का वादा किया। उन्होंने हसीना सरकार से मुक्ति पाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा किये गये आंदोलन की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ‘‘यह जनता की स्वतन्त्रता की दूसरी विजय है।’’

महत्वपूर्ण बात यह है कि यूनुस अन्तरिम सरकार के मुख्य सलाहकार होंगे, अन्तरिम प्रधानमंत्री नहीं तथा जैसा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **मोहम्मद यूसुस जानते हैं कि बांग्लादेश को अस्थिरता से निकालने और स्थायित्व की ओर ले जाने में भारत का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है।**
- **बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक यूनुस ने बांग्लादेश में गरीबों को काम काज के लिये छोटे-छोटे ऋण देना शुरु किया था। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।**
- **पर, बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना से उनकी नहीं बनी और उन पर केस ठोका गया तथा जेल की सजा भी सुनाई गई।**
- **समझा जाता है कि सेना प्रमुख, बांग्लादेश के राष्ट्रपति और छात्र नेताओं की संयुक्त बैठक में छात्र नेताओं की ओर से यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।**

एन.सी.ई.आर.टी. की किताबों से संविधान की प्रस्तावना हटाने का मामला गर्माया

राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेरा

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अगस्त। क्या ‘‘भाजपा-आर.एस.एस. की साम्प्रदायिक विचारधारा को थोपने’’ की कोशिश में एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्य-पुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना हटा दी गई है?

जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता तथा कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह मामला उठाया, तो इस प्रश्न पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा होता दिखाई दिया। सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने तुरन्त पलटवार किया और कहा कि देश में आपातकाल लगाकर, संविधान पर हमला करने का काम तो कांग्रेस ने किया था। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि जहाँ तक एन.डी.ए. सरकार का सम्बन्ध हैं, उसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना से छेड़ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

समाचार पत्र ‘द हिन्दू’ में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एन.सी.ई.आर.टी. ने हाल ही में अपनी पाठ्यपुस्तकों में कुछ परिवर्तन किये हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एन.सी.ई. आर.टी. की कुछ पाठ्यपुस्तकों से संविधान की प्रस्तावना साफ तौर पर गायब है। सरकार से स्पष्टीकरण की माँग करते हुये, खड़गे ने कहा, ‘‘चुनावों में हार के बाद, भाजपा ने पहले तो गांधी और अम्बेडकर की मूर्तियाँ हटाईं तथा संविधान के साथ छेड़ करने की कोशिशें भी कीं। इस देश की जनता ऐसा नहीं होने देगी। आर.एस.एस. और भाजपा स्कूली पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप तथा हेर-फेर करके, अपनी साम्प्रदायिक विचारधारा को थोपना चाहती हैं तथा एन.सी.ई.आर.टी. की यह चेष्टा सही नहीं है। सत्ता पक्ष के सदस्य खड़गे की टिप्पणी का जोर-शोर से विरोध करने लगे तथा नड्डा ने खड़े होकर कहा कि कांग्रेस नेता को इस सूचना का स्रोत प्रस्तुत करना चाहिये। उन्होंने कहा, ‘‘किसी अखबार के लेख को प्रमाणिक स्रोत नहीं माना जा सकता। स्रोत के रूप में, मूल पाठ्यपुस्तक ही

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर संवधिान के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए वॉक आउट किया।**
- **राज्यसभा के नेता जे.पी. नड्डा ने विपक्ष के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि मोदी सरकार की संविधान के प्रति निष्ठा संदेह से परे है।**
- **नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 1975 में आपातकाल लगा कर कांग्रेस ने अवश्य संविधान पर हमला किया था।**

गढ़ गणेश पर बनाए जा रहे रोप वे पर यथास्थिति के आदेश

जयपुर, 7 अगस्त (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने गढ़ गणेश मंदिर पर बनाई जा रही रोप-वे पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, कोर्ट ने इस मामले में जयपुर कलेक्टर, गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट और रोप वे बना रही कंपनी मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की बैंच ने यह आदेश दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लि. की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया है कि टाइगर हैबिटेट प्रबंधन में सुधार करेगी।

- **हाई कोर्ट ने यह आदेश दामोदर रोप वे एंड इन्फ्रा लिमिटेड की याचिका पर दिए, जिसने रोप वे निर्माण के लिए आवेदन किया था, पर, यह काम शिवम प्राइम इन्फ्रा को सौंपा गया, जबकि इसने आवेदन तक नहीं किया था।**

अमरावती से झाड़-झंखाड़ हटाने में 36 करोड़ रू. खर्च होंगे

आंध्र सरकार ने अमरावती क्लीन जंगल प्रोजैक्ट शुरु किया

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अगस्त। पैतृक गांव के घर की लम्बे समय उपेक्षा करने पर उसको पुनः इस्तेमाल योग्य बनाने के लिए साफ-सफाई में काफी खर्चा आता है और जरा सोचिए अगर एक पूरे शहर की उपेक्षा हुई हो तो यह कितना महंगा पड़ सकता है। अमरावती जिसे आंध प्रदेश की राजधानी बनाया जाना था, की लम्बे अर्से तक उपेक्षा की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी ने अमरावती प्रोजेक्ट त्याग दिया था, जिसे उनके पूर्ववर्ती चंद्रबाबू नायडू ने शुरु किया था। इसकी बजाय उन्होंने ‘‘थ्री कैपिटल’’ प्लान पर फोकस किया। इसका नतीजा है कि विभाजन के दस साल बाद भी आंध्र प्रदेश के पास अपनी राजधानी नहीं है।

दस साल से हैदराबाद ही तेलंगाना की संयुक्त राजधानी है और आंध्र प्रदेश अमरावती को अपनी नई राजधानी बनाने वाला था। पर पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी को अमरावती का विचार पसंद नहीं था उनके मन में तीन राजधानियों की योजना थी। इसलिए उन्होंने चन्द्रबाबू नायडू द्वारा 2016 में शुरु किए गए अमरावती प्रोजेक्ट की अवहेलना की। एन. चन्द्रबाबू नायडू अमरावती को अत्याधुनिक राजधानी बनाना चाहते थे। लेकिन जगनमोहन रेड्डी, जो 2019 में प्रधानमंत्री बने थे, ने अमरावती की उपेक्षा कर दी और इस प्रोजेक्ट को ही त्याग दिया और नायडू सरकार के कार्यकाल में वहां दो सरकारी इमारतें बन चुकी थीं। लेकिन प्रोजेक्ट रद्द होने के बाद उसकी तरफ किसी ने रुख नहीं किया नतीजा यह निकला कि वहां भारी झाड़ झंखाड़ उग आए हैं।

अब जब चन्द्रबाबू नायडू दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उन्होंने अमरावती प्रोजेक्ट के लिए केन्द्र सरकार से 15,000 करोड़ रु. भी आवंटित करवा लिए हैं। अब काम शुरु हो गया है सबसे पहले जंगल साफ करवाया जा रहा है।

कोई माने या ना माने पर सिर्फ जंगली झाड़ झंखाड़ साफ करवाने और जमीन को समतल कराने में 36 करोड़ रु. खर्च होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **चंद्रबाबू नायडू ने 2016 में अमरावती प्रोजैक्ट शुरु किया था, पर, जगन मोहन ने इसे ठुकरा दिया, नतीजतन वहां झाड़-झंखाड़ उग आए थे।**
- **2014 में जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ था और हैदराबाद, तेलंगाना के हिस्से में चला गया था तब चंद्रबाबू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित करने की योजना बनाई थी।**
- **नायडू, अमरावती को अत्याधुनिक विश्वस्तरीय राजधानी बनाना चाहते थे। यह उनका ड्रीम प्रोजैक्ट था तथा उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी थी। पर, फिर नायडू विधानसभा चुनाव हार गए और उनके बाद जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अमरावती प्रोजैक्ट को ठुकरा दिया और तीन राजधानियों की अटपटी अवधारणा दी।**
- **अब नायडू फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उन्होंने जोर-शोर से अपना ड्रीम प्रोजैक्ट शुरु कर दिया है। यही नहीं, इसके लिए उन्होंने केन्द्र सरकार से भारी अनुदान भी हासिल कर लिया है।**

एक दशक में बांग्लादेश की ‘पर कैपिटा’’ आय तिगुनी हुई: बांग्लादेश विश्व में ‘‘फास्टैस्ट ग्रोइंग इकॉनमी भी बना!

पर, इकोनॉमिक ग्रोथ, जब तक इसका लाभ प्रजातंत्रीय व्यवस्था के कारण, पूरे समाज, गरीब से गरीब जनता तक नहीं पहुंचता, एक विस्फोटक स्थिति पैदा करती है, जैसा बांग्लादेश में हुआ

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 अगस्त। वर्ष 2009, 2014, 2019 और 2024 के चार चुनाव जीतने के बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्र स्तरीय छात्र आंदोलन के बाद देश छोड़कर भाग जाना उन सभी के लिए तगड़ा झटका है जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक नियम-कायदों को समाज और राजनीति में पोषित करते हैं।

बांग्लादेश के अस्तित्व के 50 साल में हुए इस नवीनतम प्रकरण से पूरी दुनिया और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप की जनता और शासकों को कई सबक सीखने और भुलाने हैं।

पड़ोसी देश बांग्लादेश में उथल-पुथल मचने के पीछे भारी भ्रष्टाचार, स्वतंत्रता एवं अधिकारों का कमजोर पड़ना, साथ-साथ तेजी से हुई आर्थिक वृद्धि, कुछ ही लोगों के हाथों में धन-सम्पदा का एकत्रित होना और सरकार द्वारा कुछ चहेते लोगों को ही आगे बढ़ाना प्रमुख कारण हैं। शेख हसीना भी अपनी स्वयं की ही दुश्मन हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसी विरासत को बरबाद कर दिया, जो उनकी मुख्य राजनीतिक पूंजी थी।

उनकी अधिनायकवादी सरकार असंतोष के स्वरों को दबाने के लिए प्रतिबद्ध थी, तथा उनके नेतृत्व की तानाशाह शैली ने विपक्ष को नियंत्रण में रखने का हर उचित एवं अनुचित माध्यम अपनाया और यह शैली उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की कार्यशैली के विपरीत थी जिन्होंने बांग्लादेश के निर्माण को लेकर संघर्ष किया।

हसीना वर्ष 2009 में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय चुनाव के बाद सत्ता में आई थीं, लेकिन उसके बाद वर्ष 2014, 2018 और 2024 में हुए चुनाव विवादास्पद रहे और उनमें विपक्ष की भी भागीदारी नहीं रही, लेकिन हसीना इसके बावजूद देश की प्रधानमंत्री बनीं। इन चुनावों में वह अपराजेय सी लगीं और उन्होंने सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष अथवा असंतोष को बिल्कुल सहन नहीं किया, जबकि लोकतांत्रिक संरचना के यही दो आवश्यक अवयव होते हैं।

बांग्लादेश के स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों के वंशजों के लिए हाई कोर्ट द्वारा नौकरियों में 30 प्रतिशत कोटा बहाल किए जाने के बाद आंदोलनकारियों के सब्र का बांध टूट गया, हालांकि हसीना के शासन के खिलाफ पिछले कई वर्षों से जनता का क्रोध पनप रहा था। देश की आम जनता ज्यादातर बेरोजगार है और उपद्रवों से वह भयभीत हो गई। शेख हसीना ने जब अदालती प्रक्रिया का हवाला देकर छात्रों की मांगे मानने से इन्कार कर दिया, तब संकट गहरा गया।

हसीना की सबसे बड़ी गलती तब हुई, जब उन्होंने नौकरियों में आरक्षण का विरोध करने वालों को रज़ाकार (बांग्लादेश के एक अप्रिय शब्द) करार दिया। वर्ष 1971 में हुए बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में पाकिस्तान की सेना का सहयोग करने वालों के लिए यह शब्द प्रयुक्त किया गया था, जिससे हजारों आंदोलनकारी छात्र बुरी तरह से चिढ़ गए।

विपक्ष ने हसीना पर हमेशा यह आरोप लगाया कि उन्होंने लगातार तीन चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के बिना जीते हैं। इसके अलावा एक आम धारणा यह भी थी कि आर्थिक विकास केवल हसीना की आवामी लीग के निकट के लोगों का भला करने के लिए ही है।

विरोध प्रदर्शन जैसे-जैसे बढ़ते गए, उन्हें अभिभावकों, शिक्षकों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिलता गया। आंदोलन अपनी शुरुआती मांगों से आगे बढ़कर 15 वर्षों के भय एवं उत्पीड़न के खिलाफ निराशा की एक लामबंद अभिव्यक्ति बन गया। छात्रों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत से तब तक के लिए इन्कार कर दिया, जब तक कि उनकी मांगें नहीं मान ली जातीं। इससे सरकार के प्रति जनता के गहरे अविश्वास का पता चलता है। देश के सेवारत और सेवानिवृत्त शीर्ष अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर खुली चर्चाएं थीं। तथापि, हसीना ने भ्रष्टाचार को एक समस्या के रूप में स्वीकार किया था और उसके खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था, लेकिन ठोस कार्रवाई कहीं नज़र नहीं आ रही थी।

बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, वह उन देशों के लिए भी एक सबक है जो समाज का व्यापक हित न सोचकर केवल आर्थिक प्रगति का राग अलापते रहते हैं और यह भी कि लोकतांत्रिक मूल्यों एवं नागरिकता के क्षरण के बीच सिर्फ आर्थिक प्रगति ही किसी नेता की लोकप्रियता को ज्यादा समय तक नहीं बनाए रख सकती।

निःसंदेह, हसीना के कार्यकाल में शानदार आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त की गईं। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश विश्व के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- **इकोनॉमिक समृद्धि का फायदा हसीना सरकार के मित्रों तक ही सीमित रहा तथा शिक्षित युवकों में बेरोज़गारी वैसी की वैसी ही बनी रही।**
- **शिक्षित बेरोज़गारों के आक्रोश को दबाने के लिये हसीना सरकार ने पूरी सख्ती बरती और असंतोष अंदर ही अंदर बढ़ता रहा।**
- **इकोनॉमिक ग्रोथ के लिये विपक्ष के मतभेद तथा असंतोष की अभिव्यक्ति, जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था के लिये अनिवार्य है, को कुचला गया, अतः नौबत यह हुई कि प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा।**